तेजयुग न्यूज सम्पादकीय
www.tejyug.com
epaper.tejyug.com

>> विचार

हमारे संविधान में प्राचीन भारत में हुए अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित कानून आज की तारीख में भी दुनियाभर के लिए विशेष आदर का विषय हैं। वे लोगों को स्वभाविक रूप से उनका पालन करने और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सन् 1998 में सत्ता में आने के बाद जो पहला काम किया वह था संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति। इस आयोग (वेंकटचलैया आयोग) की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी क्योंकि संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का जबरदस्त विरोध हुआ। बीजेपी अपने बल पर 2014 से सत्ता में है और तब से उसने कई बार संविधान की उद्देशिका का प्रयोग, उसमें से धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द हटाकर किया है। सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बनने के बाद के। सुदर्शन ने बिना किसी लागलपेट के कहा था कि भारत का संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और उसके स्थान पर एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जो भारतीय पवित्र ग्रन्थों पर आधारित हो।

बीजेपी शासन भारतीय प्रजातंत्र और संविधान के लिए खतरा!

राम पुनियानी

सत्ताधारी बीजेपी के नेता इन दिनों 'चार सौ पार' की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले आम चुनाव में बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उसके गठबंधन साथी 30 से ज्यादा। और इस प्रकार एनडीए 400 पार हो जायेगा। यह संख्या किसी चुनाव विशेषज्ञ की राय या किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। यह प्रचार केवल राजनैतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। चार सौ पार की जरूरत क्यों है? इसका स्पष्टीकरण देते हुए बीजेपी के कर्नाटक से सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े ने बताया कि संविधान को बदलने के लिए पार्टी को 400 सीटों की जरूरत होगी। ''कांग्रेस ने संविधान को विकृत कर दिया है। उसका मूल स्वरूप बदल दिया है। उसने संविधान में अनावश्यक चीजें (शायद उनका मतलब धर्मनिरपेक्षेता और समाजवाद से था) ठूंस दी हैं। ऐसे कानून बनाए गए हैं जो हिन्दू समुदाय का दमन करते हैं। ऐसे में अगर इस स्थिति को बदला जाना है, अगर संविधान को बदला जाना है, तो वह उतनी सीटों से संभव नहीं है जितनी अभी हमारे पास हैं। बीजेपी ने इस बयान से दूरी बना ली। उसने कहा कि वह अपने सांसद के वक्तव्य का अनुमोदन नहीं करती। ऐसी खबरें भी हैं कि यह बयान देने के कारण हेगड़े को पार्टी के टिकिट से भी वंचित किया जा सकता है। ऐसा होता है या नहीं यह तो समय बतलायेगा मगर एक बात पक्की है। वह यह कि बीजेपी के लिए इस तरह के बयान और दावे कोई नई बात नहीं हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने यही बात 2017 में भी कही थी जब वे बीजेपी की केन्द्र सरकार में मंत्री थे। मगर फिर भी उन्हें 2019 के आम चुनाव में टिकिट दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कई अन्य का मानना है कि बीजेपी को 400 सीटें उसी उद्देश्य के लिए चाहिए, जिसकी बात हेगड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिन्दी में लिखा, ''बीजेपी सांसद का यह बयान कि पार्टी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत होगी, दरअसल, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के गुप्त एजेण्डा की सार्वजनिक उद्घोषणा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम उद्देश्य बाबा साहेब के बनाए संविधान को नष्ट करना है। संघ परिवार न्याय, समानता, नागरिक अधिकार और प्रजातंत्र जैसी संकल्पनाओं से नफरत करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि ''समाज को बांटकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोकें लगाकर और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु कर संघ परिवार भारत के महान प्रजातंत्र को एक संकीर्ण तानाशाही में बदल देना चाहता है और एक षड़यंत्र के तहत विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों, जिनमें समानता का मूल्य शामिल है, को कमजोर करने के लिए बीजेपी की रणनीति द्विस्तरीय है। उसका पितृसंगठन आरएसएस शुरू से ही संविधान के खिलाफ रहा है। भारत का संविधान लागू होने के बाद आरएसएस के गैर-आधिकारिक मुखपत्र 'द आर्गनाईज़र' ने लिखा। ''हमारे संविधान में प्राचीन भारत में हुए अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नही है। मनुस्मृति में वर्णित कानून आज की तारीख में भी दुनियाभर के लिए विशेष आदर का विषय हैं। वे लोगों को स्वभाविक रूप से उनका पालन करने और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सन् 1998 में सत्ता में आने के बाद जो पहला काम किया वह था संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति। इस आयोग (वेंकटचलैया आयोग) की रिपोर्ट लागू नही की जा सकी क्योंकि संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का जबरदस्त विरोध हुआ। बीजेपी अपने बल पर 2014 से सत्ता में है और तब से उसने कई बार संविधान की उद्देशिका का प्रयोग, उसमें से धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द हटाकर किया है। सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बनने के बाद के। सुदर्शन ने बिना किसी लागलपेट के कहा था कि भारत का संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और उसके स्थान पर एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जो भारतीय पवित्र ग्रन्थों पर आधारित हो। सुदर्शन ने कहा कि संविधान भारत के लोगों के लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संविधान को पूरी तरह से बदल डालने में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी पिछले साल अगस्त में 'लाईवमिंट' में प्रकाशित अपने एक लेख में प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के मुखिया डॉ। विवेक देबराय ने भी संविधान को बदलने की जरूरत बताई थी। इस प्रकार बीजेपी संगठन और सरकार के प्रमुख कर्ताधर्ता समय-समय पर संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं और बीजेपी और सरकार, आधिकारिक रूप से कहती रहती है कि वह इन विचारों का अनुमोदन नही करती। इसके साथ ही अपनी सरकार के पिछले एक दशक के शासनकाल में बीजेपी ने भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्यों को क्षति पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया है। प्रजातांत्रिक राज्य के सभी स्तम्भों और संवैधानिक संस्थाओं सहित सभी एजेन्सियों पर सरकार का नियन्त्रण है। सरकार का मतलब है एक व्यक्ति। चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर विभाग या चुनाव आयोग हो - सभी एक व्यक्ति के नियंत्रण और निर्देशन में काम कर रहे हैं। जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है उसे भी अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग तरीकों से कमजोर कर दिया गया है। वरना आखिर क्या कारण है कि उमर खालिद के तीन साल से जेल में होने के बावजूद कोई अदालत उसकी जमानत की अर्जी पर विचार करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है वह लगभग गायब हो चुकी है। मुख्यधारा का मीडिया सरकार के प्रशंसक कार्पोरेट घरानों के नियंत्रण में है और सभी बड़े टीवी चैनल और अखबार सरकार के भोंपू बन गए हैं। स्वतंत्रता से सोचने वाले और आज़ादी से बोलने वालों के लिए बहुत कम जगह बची है और यह तब जब हम सब जानते हैं कि बोलने की आज़ादी प्रजातांत्रिक समाज का प्रमुख स्तंभ है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के अनुसार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कमज़ोर होती जा रही है। अमरीका के धार्मिक स्वतंत्रता वॉचडॉग के अनुसार भारत ''विशेष चिंता'' का विषय है। वी-डेम के अनुसार प्रजातंत्र के सूचकांक पर भारत का नंबर 104 है और वह नाईजर और आईवरी कोस्ट के बीच है। यह गिरावट पिछले दस सालों में ही आई है। सरकार अपनी एजेंसियों और अपने निर्णयों के जरिये प्रजातांत्रिक स्वतंत्रताओं का गला घोंट रही है। बहुत समय नहीं हुआ जब लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू है। देश में हिन्दू राष्ट्रवाद के लड़ाके हर तरह की आज़ादी को कुचल रहे हैं। सरकारी तंत्र भी यही कर रहा है। सरकार दर्शक दीर्घा में है और इन तत्वों को उसका साफ संदेश है कि वे अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम अपने आसपास देखें तो पायेंगे कि हर धार्मिक राष्ट्रवादी संस्था को प्रजातांत्रिक स्वतंत्रताओं से एलर्जी होती है। वे सभी संविधान को बदलना चाहते हैं और उनके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर बांटने और दमन करने वाली राजनीति करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में यही होता आया है। अब भारत भी प्रजातंत्र को कुचलने वाले देशों के इस क्लब में शामिल होने की कोशिश में है। बीजेपी की रणनीति साफ है- एक ओर संविधान को बदलने की बात करो और दूसरी तरफ जो संविधान अभी है उसे कमज़ोर और निष्प्रभावी कर दो।

संपादकीय

नशे के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलना होगा

हाल के दिनों में देश के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हमारे नीति नियंताओं की गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। ये घातक नशा न केवल युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करता है बल्कि अपराध की एक अंतहीन श्रृंखला को भी जन्म देता है। जाहिर तौर पर नशे के अंतर्राष्ट्रीय सौदागर देश में कानून-व्यवस्था का संकट भी पैदा करना चाहते हैं। यह संकट कितना बड़ा है, वह इस बात से पता चलता है कि एक माह के भीतर भारतीय एजेंसियों ने गुजरात तट पर नशे की एक दूसरी बड़ी खेप बरामद की है। एनसीबी, तटरक्षक बल व गुजरात आतंकरोधी दस्ते के साझे अभियान को तब बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब पोरबंदर तट पर करीब 480 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ जब्त किया गया। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के लिये काम करने वाले छह पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी भी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिये समुद्र मार्ग से हो रही नशीले पदार्थों की बड़ी तस्करी के सूत्र तलाशने में भारतीय एजेंसियों को मदद मिल सकेगी। ज्यादा दिन नहीं हुए जब पिछले महीने ही गुजरात के तट पर एक ईरानी नाव से तैंतीस सौ किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किये गए थे। गाहे-बगाहे देश के अन्य भागों से भी नशीले पदार्थों की बरामदगी की खबरें मिलती रहती हैं। अकेले गुजरात से ही पिछले दो सालों के दौरान करीब छह हजार करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस आंकड़े से इस बात का अहसास किया जा सकता है कि पूरे देश में नशीले पदार्थों की बरामदगी का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। यह भी कि देश की युवा पीढ़ी को तबाह करने की कितनी बड़ी साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है। बड़ी बरामदगियों में पाकिस्तान, ईरान व अफगानिस्तान की भूमिका से गहरी साजिश की ओर इशारा मिलता है। निश्चित रूप से ड्रग्स से हासिल रकम का उपयोग पूरी दुनिया में आतंकवाद की जड़ें सींचने में किया जा रहा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में ड्रग्स की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। निस्संदेह, देश में जब भी कहीं कोई नशे की बड़ी खेप की बरामदगी होती है आम भारतीय की फिक्र बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए कि यदि हाल में बरामद ड्रग्स की खेप भारत में दाखिल होती तो कितने युवा पथभ्रष्ट होते? वहीं देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में आतंकवाद को सींचने के लिये चली जाती। हमें न केवल बाहर से आने वाली नशे की खेपों पर अंकुश लगाना है, बल्कि उन काली भेड़ों पर भी लगाम कसनी है जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की मददगार बनी हुई हैं। हमें देश के भीतर नशे सप्लाई करने वाले तंत्र की जड़ों तक भी पहुंचना होगा, अन्यथा हजारों घरों के चिराग असमय काल-कवलित होते रहेंगे। देश के विभिन्न भागों से नशे की ओवर डोज से मरने वाले युवाओं की खबरें अकसर आती रहती हैं। अपनों को खोने वाले परिवारों की पीड़ा को देश के नीति-नियंताओं को समझना होगा। नशे की इस भयावह लत का एक घातक पहलू यह भी है कि यह समाज में कई तरह के अपराधों को भी जन्म देती है। विगत में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि जब महंगे नशीले पदार्थों को खरीदने के लिये युवा अपराध की तंग गलियों में विचरण करने लगते हैं। कई सोने की चेन छीनने की घटनाओं में तमाम ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो अच्छे खाते-पीते घरों के थे, कई अच्छे शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत थे। संकट का एक पहलू पड़ोसी देश पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों की भूमिका भी है। जम्मू-कश्मीर व पंजाब में ड्रग मनी का इस्तेमाल आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने तथा भारत विरोधी अभियान चलाने में किया जाता है। यहां तक कि सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी के बाद अब ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थ सीमावर्ती जिलों में गिराये जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने ऐसे कई ड्रोन मार भी गिराए जो नशे की खेप लेकर भारतीय सीमा में घुस रहे थे। निश्चित रूप से यह बड़ा संकट है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार व उसकी खुफिया एजेंसियों को नियोजित ढंग से नशे के नापाक कारोबार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलना होगा।

बीजेपी ने जगन रेड्डी के बजाय चंद्रबाबू के साथ क्यों किया गठबंधन!

समीर चौगाओंकर

2024 के लोकसभा चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी दक्षिण के राज्य आंध्रप्रदेश में गठबंधन का साथी पाने में सफल रही है। 6 साल बाद एक बार फिर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू सारे गिले-शिकवे भुलाकर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। 9 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी के मुखिया पवन कल्याण की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी कर कहा गया था कि तीनों दलों में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। बीजेपी 6 लोकसभा और 10 विधानसभा, तेलगुदेशम पार्टी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा और पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेलगुदेशम पार्टी और जनसेना के साथ बीजेपी के जुड़ जाने से बीजेपी को फ़ायदा होना तय है, क्योंकि बीजेपी को आंध्र प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में इखढ का वोट शेयर आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम रहा था, और नोटा से भी कम वोट मिला था। बीजेपी को भरोसा है कि गठबंधन में शामिल होकर वह अपनी स्थिति आंध्र प्रदेश में सुधार सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार, तेलगुदेशम के कमजोर होने और कांग्रेस के लगभग ख़त्म होने के बाद भी उसकी स्थिति मजबूत नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए राज्य में जगह नहीं बन पा रही है। दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश ही बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी बना रहा। आंध्र प्रदेश से टूटकर बने तेलंगाना में बीजेपी ने अपना आधार तैयार कर लिया है और पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें भी जीत ली थी। कुछ माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी ने अपने वोट बैंक में शानदार बढ़ोतरी कर ली। दक्षिण के एक और राज्य तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने जिस तरह से एआईएडीएमके से गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण जगा दी है, वैसा नेता आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मिल नहीं सका। हालाँकि बीजेपी ने एनटी रामाराव की बेटी और चंद्रबाबू की साली पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसे में बीजेपी के पास भी चंद्रबाबु नायडू से हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। गठबंधन को लेकर आंध्र प्रदेश भाजपा में दो तरह की सलाह केंद्रीय नेतृत्व को मिल रही थी। एक गुट का मानना है कि चंद्रबाबू नायडू भरोसे वाले नेता नहीं हैं और बीजेपी को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। ये नेता, पवन कल्याण की पार्टी से गठबंधन के पक्ष में तो थे, लेकिन नायडू के साथ जाने के पक्ष में नहीं थे। आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसा भी गुट था जिसने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को सलाह दी कि अगर आंध्र प्रदेश में कुछ भी हासिल करना है तो गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है और इससे प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। बीजेपी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बन रहे माहौल को भांप रही थी और यह मान कर चल रही है कि जगनमोहन से नाराज़गी का पूरा फ़ायदा नायडू को मिलेगा। ऐसे में टीडीपी राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है अतः चन्द्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाना उसके लिए फायदे का सौदा होगा। वाईएसआरसीपी के ख़िलाफ़ बन रही हवा को भांपते हुए ही बीजेपी ने टीडीपी के साथ जाने का निर्णय लिया है। चंद्रबाबू नायडू की भी राजनीतिक मजबूरी थी कि वो बीजेपी के साथ जुड़कर पुनः एनडीए में आ जाएं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी। 1996 के लोकसभा चुनावों के पहले नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हो गए थे और तब से लेकर 2018 तक एनडीए का हिस्सा रहे। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी न होने पर चंद्रबाबू ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। वो मांग अभी भी अधूरी है, लेकिन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से चंद्रबाबू को केंद्रीय एजेंसियों का भी डर है। उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ जाने से वो कानूनी कार्रवाई से बचे रहेंगे। गौरतलब है कि बीते साल सितंबर में आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले चुनाव में तगड़ा नुक़सान उठा चुकी टीडीपी को लगता है कि मोदी और शाह की मदद से जगनमोहन के सामने मजबूती से खड़ा हुआ जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू को ये भी पता है कि मोदी और जगनमोहन के बीच बुरे संबंध नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन होने से टीडीपी आंध्र प्रदेश की जनता को ये संदेश देने में भी सफल रहेगी कि केंद्र सरकार उसके पक्ष में है। 2014 में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में 2 लोकसभा सीट और विधानसभा में 4 सीट जीती थी। तब बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन में थी। 2019 में गठबंधन टूटा तो लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का खाता नहीं खुला। इसलिए चंद्राबाबू के साथ जाकर पार्टी जहां राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है वही दूसरी ओर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन और केजरीवाल की तरह ईडी और सीबीआई के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए केंद्र से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं और राज्यसभा में हरसंभव मदद बीजेपी की करते हैं। बीजेपी दक्षिण में कांग्रेस को किसी भी स्थिति में ज़िंदा नहीं होने देना चाहती हैं और इस कारण सभी को साधकर चल रही है। मोदी का लोकसभा में 370 सीटों का लक्ष्य बिना दक्षिण को साधे संभव नहीं हैं। ऐसे में दक्षिण का एक-एक सहयोगी दल बीजेपी को उसके लक्ष्य में मदद कर सकता है। बीजेपी का लक्ष्य साफ़ है जहां अपने पैरो पर नहीं खड़े हो सकते हैं वहाँ दूसरों के सहारे आगे बढ़ें। इसलिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी दोनों प्रमुख दलों को साधकर चल रही है। चुनाव भले ही टीडीपी और पवन कल्याण के साथ लड़ रही है लेकिन चुनाव के बाद जगनमोहन के साथ भी बीजेपी जा सकती है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव परिणाम तय करेगा कि बीजेपी किस नाव की सवारी करेगी।

41 साल के टीएमसी सांसद की सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड ने उड़ाए होश

पूर्णिमा आचार्य

लोकसभा चुनाव 2024 इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। आम लोगों से लेकर वीआईपी नेताओं तक सभी चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में कई पुराने नेताओं से लेकर बड़े बड़े सेलेब्स के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव यानी दीपक अधिकारी। पश्चिम बंगाल के घाटाल लोकसभा सीट के सांसद देव देव पश्चिम बंगाल के घाटाल लोकसभा सीट से टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के प्रत्याशी हैं। वह पहले भी इसी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम टीएमसी के प्रत्याशी देव की नही बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड रुक्मिणी मित्रा की बात करेंगे। देव की तरह की उनकी गर्लफ्रेंड भी एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं और करोड़ों में कमाई करती हैं। देव की सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड रुक्मिणी मित्रा रुक्मिणी मित्रा भारतीय मॉडल होने के साथ साथ एक शानदार एक्ट्रेस भी हैं। कोलकाता में जन्मी रुक्मिणी ने बांग्ला फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक में शानदार काम किया है। हाल ही में वह विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की फिल्म 'क्रैक' में एक आइटम नंबर करती नजर आई हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की करोड़ों की संपत्ति उड़ा देगी बॉलीवुड हीरोइनों की नींद, जानें कितनी है कमाई बॉलीवुड फिल्मों में करती हैं काम रुक्मिणी मित्रा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2017 में एक बांग्ला फिल्म 'चैंप' से की थी। इसके बाद वह साल 2021 में बॉलीवुड फिल्म 'सनक' में बतौर हीरोइन नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ विद्युत जामवाल ने काम किया था। 40 करोड़ की संपत्ति की हैं मालकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें रुक्मिणी मित्रा की कुल संपत्ति 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास है। रुक्मिणी मित्रा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। वह रिलायंस, लैक्मे, वोडाफोन, सनसिल्क, पैराशूट, टाइटन, टाटा टी, राडो, एले, हार्पर बाजार, फेमिना, रॉयल स्टैग, पीसी चंद्रा ज्वैलर्स, भीमा सहित कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और प्रकाशनों के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में आ चुकी हैं नजर इसके अलावा रुक्मिणी मित्रा सेन्को गोल्ड, स्पेंसर, आईटीसी, फियामा डि विल्स, बिग बाजार, लक्स और इमामी के विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं। मॉडलिंग और फिल्मों के जरिए रुक्मिणी की करोड़ों में कमाई होती है। रुक्मिणी मित्रा के बड़े भाई उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। ऐसे में देव और रुक्मिणी यही यूपी में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। रुक्मिणी ने 13 साल में की थी मॉडलिंग की शुरुआत रुक्मिणी मित्रा ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी। उन्होंने मसाबा गुप्ता, अनीता डोंगरे, सुनीत वर्मा, देव आर निल, अंजू मोदी जैसे फेमस फैशन डिजाइनरों के अलावा कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी कंपनियों के लिए रैंप वॉक भी किया है।